बातचीतकेबिंदु-03

मजदूर –किसानसंघर्षरैली

सीटू-अखिलभारतीयकिसानसभा-अखिलभारतीयखेतमजदूरयूनियन

5 सितम्बर 2018

संसदकेसमक्ष

रोजगार

बीजेपी जिसका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी थे, का मुख्य वायदा था कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। पिछले 10 सालों से यूपीए के शासनकाल में रोजगार विहीन विकास के कारण जनता ने इसका दिल से स्वागत किया। इसके 4 साल बाद यह पाया कि मोदी अपने वायदे पर खरा नहीं उतरे। (उसने पहले की सरकार की तर्ज पर नीतियां लागू की इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं हुई कि वो वादा पूरा नहीं कर सके। असलियत में हालात पहले से भी गंभीर हुए है क्योंकि लोगों ने रोजगार खोये हैं। अब यहॉ विकास हुआ है लेकिन रोजगार में कटौती हुई है।रिजर्वबैंककीरिपोर्ट के अनुसार मोदी के पहले दो साल के शासन में 10 लाख रोजगार घटे हैं। 2014–15 में देश में काम करने वालों की संख्या 7.7 लाख कम हुई और 2015–16 में 3.8 लाख और कम हो गई। इसके बाद चीजे बद से बदतर हो गई, पिछले 15 सालों या उसके ऊपर 2016 में लगभग 43 प्रतिशत लोग ही रोजगार पर थे। सी एम आई ई के अनुसार 2018 में हालात और बिगड़ गए और यह हिस्सा 40 प्रतिशत तक गिर गया। जिसका मतलब है कि 1.43 करोड़ कामगार नौकरियां खो चुके है। लेवर ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में महिलाओं के रोजगार की स्थिति कमजोर बनी हुई है। यह 15 साल या उससे ऊपर की महिलाओं के 22 प्रतिशत का ही रोजगार मिल पाया है। यह पूरे विश्व में सबसे कम है।

लेवर ब्यूरो के आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का त्रैमासिक सर्वे अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2017 दर्शाताहैकि 8 महीनोंमेंमात्र 5.56 लाख रोजगारही बढ़ पाए इससेनिष्कर्षनिकलताहैकि श्रम शक्ति का केवल 1.8 प्रतिशत सालाना 4 लाख रोजगार ही बढ़ पाए। अगर दूसरे श्रेणी में रोजगार घटे हैं तो यह और भी घट जाएगा। सी एम आई ई के अनुभवों के अनुसार बेरोजगारी 5 प्रतिशत हो गई है। इसका मतलब है कि 2 करोड़ लोग लेवर ब्यूरो की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत श्रम शक्ति पूरे साल काम नहीं मिलता या उन्हें बहुत कम रोजगार पर काम करने पर मजबूर किया जाता है। यह संख्या लगभग 13 करोड़ है।

इसी कारण से हमे चौकाने वाली रिपोर्ट मिलती है कि रेलवे में 1 लाख रिक्त स्थानों के लिए 2.5 करोड़ लोग आवेदन पत्र देते है या उत्तर प्रदेश में 368 चपरासी के लिए 23 लाख अर्जियां (आवेदन) आती है, हरियाणा की कोर्ट में 9 पदों की भर्ती के लिए 18,000 आवेदन आते है,राजस्थान के सचिवालय में 18 पदों के लिए 12000 आवेदन आते है।

रोजगार को समाप्त करने वाली सरकार

सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र भारत में पूरे रोजगार का बहुत कम हिस्सा उत्पन्न करते है। लेकिन सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में अनवरत रोजगार गिरावट दर्शाते है कि मोदी सरकार रोजगार पैदा करने वाली नहीं है यह तो रोजगार बर्बादी करने वाली है।

जब से यह सरकार 2014 में आई है, सभी सरकारी महकमों (मंत्रालयो, रेवले, पोस्टल, विभाग,पोलिस इत्यादि) में नौकरियों में लगतार गिरावट आई है। 2014 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों कि संख्या 33.28 लाख थी 2015 में घटकर 33.06 रह गई, 2016 में 32.85 लाख और 2017 में इसमे और गिरावट की गई, और यह 32.53 लाख रह गई। यह सारी स्थितियां केन्द्र के बजट दस्तावेजोंमेंदर्शायीगयीहै। 2017 में लगभग 75,000 सरकारी नौकरियां लुप्त हो गई और यही स्थिति अभी भी जारी है।

इसके अतिरिक्त 330 सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान जिनमें 2014 में 16.91 लाख लोग काम करते थे। इनके मुख्य उद्योग है मानव वाणिज्य,स्टील तेल और भारी और मध्यम इंजीनियरिंग उद्योग व उर्वरक इत्यादि। 2017 में यह सिकुड़कर 15.24 लाख रह गय जिसका अर्थ है कि 3 सालों में लगभ 1 लाख 67 हजार रोजगार खोना।

सबसे बड़ी कमी गैर–अधिकरीगण क्षेत्रों में हुई है यहां कुशल कारीगरों में 1.11 लाख की कमी और अकुशल कारीगरों में 77,000 की कमी हुई। इनमें के कुछ (पद) स्थान केजुअल और ठेका मजदूरों से भरे गए जिनकी संख्या 2014 में 3.4 लाख से बढ़कर 2017 में 3.93 लाख हो गई (यह सरकारी आंकड़े) सार्वजनिक क्षेत्र में कम रोजगार व अनियमित रोजगार मोदी सरकार का देश के लिए तोहफा है।

सरकारी बैंकों में शुरुआत में रोजगार वृद्धि हुई जो 2014 में 7.25 लाख से 2015 में 9.47 लाख हुई। इसके बाद मोदी सरकार ने बैंकों के पेंचकसेंऔरअगलेदो सालों 35000 रोजगार की कटौती कर सरकारी बैंकों में कुल संख्या के 9.12 लाख कर दिया गया। (आर बी आई डाटा)। कलर्कों और निचले स्तर की नौकरियों में कटौती की गई।

उद्योगऔरनिर्माण क्षेत्रमेंसंकट

उद्योग व निर्माण क्षेत्र रोजगार हानी से बुरी तरह प्रभावित हुए। 21 वीं सदी के पहले दशक में निर्माण क्षेत्र में हर वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि हुई। बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में यह औसत 4 प्रतिशत हर वर्ष से नीचे रही। इसके परिणाम स्वरुप इस क्षेत्र मेंगांवसेउजड़े हुए खेतीहर मजदूर रोजगारपातेथे,इसमेंभारीहानिहुई है।

इस दशक में औद्योगिक विकास बहुत ही कमजोर रहा लेकिन बीजेपी सरकार भी इस स्थिति में कोई भी बदलाव लाने में सफल नहीं रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि औद्योगिक उत्पादन मेंऊँच व नीचरही 2014–15 में 3.8 प्रतिशत थी। 2015–16 में 2.8 प्रतिशत तकगिरगई,यह 2017–18 में 4.5 प्रतिशत हुई।

इस सरकार के दो साल में कुल फैक्ट्री रोजगार 7.61 लाख बढ़ा जो कि 2011–12 में 7.36 लाख था।

नोटबंदी और जी एस टी

नोटबंदीऔरजी एस टीके कारणअर्थव्यवस्थाआनेवालेदो साल के लिए तितरबितररहेगी (विघटित)। पहलेसेबुरी हालात में असंगठित क्षेत्र काउत्पादनइससेबुरीतरहसेप्रभावित हुआ है। यह क्षेत्र पहलेसेहीरोजगारसृजन नहीं कर पा रहा था।

सरकार की योजनाएंजैसेकिस्किल इंडिया(प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) पूरी तरह से फेल हुई है इससे कोई हैरानी नहींहोती, तो3 सालमें 41.3 लाख लोगों के प्रशिक्षण दिया और उनमें से मात्र 6.15 लाख को रोजगार मिल मिल पाया क्योंकि रोजगार हैं ही नहीं।

भारत सरकार ने 4.6 लाख करोड़ लगभग 10.38 करोड़ रू कालोगोंकोमुद्राकर्ज दिया इसके आधार पर सरकार कह रही है कि लोग स्वरोजगार में लगे हैं। यह कर्जा लगभग 44000 प्रति व्यक्ति पड़ता है शायद मोदी जी के कथन अनुसार इससे पकौड़े बेचे जा सकते है।

रोजगार का संकट गहराते कृषि संकट के कारण है

भारत वर्ष मे परम्परागत रुप से कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार का स्रोत है। इसमें दोनों तरह के स्वरोजगार के वेतन भोगी श्रेणियां आती है। खेती की बढ़तीउपलब्धतानहींहोने के कारणजैसे–जैसेज्यादातर किसान जमीन को खोरहेहै,ज्यादासेज्यादालोग खेतीसे भगाएं गए है और उन्हें दूसरा कोई काम ढूढ़ने पर विवश किया गया है। बीजेपी ने खेती की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का वायदा किया था। असलियत में किसानों की आमदनी कम हुई है, ग्रामीणवेतनथम गए हैतथा रोजगार कम होने के कारण लोगों को बेरोजगारी की सेना में धकेला जा रहा है।

खेती का गहराता संकट का प्रभाव केवल खेती संबंधी रोजगार पर नहीं पड़ता। उसका असर खेती के बाहर भी पड़ता है। जैसेहीरोजगारढूढ़ने वालो की संख्या बढ़तीहैमालिकलोग कमसे कमवेतनपरकाम करवाते है।

कम वेतनतथाकृषिंसंकट का अर्थ है कि मेहनतकशआवाम की क्रय शक्ति कम होती है और मांग कम होने से पहले से खराब हालात में अर्थव्यवस्था में रोजगार कम होगे। रोजगार छीनने से वेतन कम होनेसेक्रय शक्ति कम होती है। इससे उत्पादन कम होगा और कुछ लोग रोजगार खोएगें। बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था की इसकुचक्रमें धकेलदियाहै।

सरकार ने शायद यह समझा था कि मेक इन इंडिया जैसी नीतियों से निर्यात बढ़ाने से उत्पादन बढ़ेगा। पिछले 4 सालों में गैर तेल को छोड़कर बाकी के मदो में निर्यात बिल्कुल गतिहीन (रुका पड़ा) है। जिसके कारण उत्पादन और रोजगार बिल्कुल नही बढ़ पाया। दूसरी तरफ हमारे घरेलू उत्पादनसेमुकाबलाकरनेवालेउत्पादों की आयात के कारण स्थानीय उद्योगों का नुकसान हुआ और लोगों को रोजगार खोना पड़ा।

बेरोजगारी समस्या क्यों ?

मोदी सरकार कारपोरेट के विकास व उनके लाभ बढ़ाने के लिए दृढ़तापूर्वकप्रतिबद्ध है।इसीकारणवेसार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ानानहींचाहतीउलटेइस क्षेत्र कोमारनेपरअमादाहै।इस सरकार को अमीरो को कर नहीं लगाया और सरकारी खर्चा भी नहीं बढ़ाया।उसने विपरित सरकार ने उम्मीद की किनिजी क्षेत्र रोजगार बढ़ायेगा और जिन्हें रोजगार नहीं मिलेगा वो स्वरोजगारढूंढेगें।क्योंकि सरकार अतिरिक्त खर्चाकरनानहींचाहतीथीइसलिए मांगनहीं बढ़ी।

इसके स्थान पर सरकार की नीतियों से

क)कृषि संकट और गहराया।

ख) स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ने को रोका गया क्योंकि यह सरकारनिजी क्षेत्र के मुनाफे को बढ़ाना चाहती है। इस सरकार ने जो थोड़ा बहुत खर्च किया भी है जिसे बीमा के किस्तों से निजी बीमा कम्पनियों की तिजोरी भरने के काम आया था। मेक इन इंडिया व स्किल इंडिया जैसी विनाशक योजनाओं में किया गया। यहां तक लाभप्रद रोजगार का प्रश्न है पिछले 4 साल पूरी तबाही(बर्वादी) के साल रहे हैं।

5 सितम्बर, 2018 को संसद पर ''मजदूर किसान रैली'' इन नीतियों के खिलाफ है जो रोजगार विहीन विकास कर रहा है, जोज्यादाजनता की क्रय शक्ति कम करके उत्पादन कम कर रही और ज्यादा लोगों कारोजगारछीनरहीहै।

यहरैलीसरकारसेमांगकरने के लिए हैकिदेश के मेहनतकशआवाम की कीमतपरजोनीतियांबड़ेदेशीविदेशीकारपोरेटकोलाभपहुँचाने के लिए हैउन्हेंबदलाजाए।हमइसरैली के माध्यम सेमांगकरतेहैकिसरकारअच्छेरोजगारपैदाकरने की योजनाबनाएं। उन सभी के लिए जोकामकरनाचाहतेहै खासतौरपरहमारेनौजवान।

आओमिलकरसंघर्षकरे!

- ऐसीसरकारजो 0.1 प्रतिशत के कामकरेनहींचलेगी।
- ऐसीनीतियों के लिए जो 99.9 प्रतिशतकोलाभपहुँचाए।